सर्वोत्तम शासित राज्य का सच

गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार तथा कथित रूप से राजीव गांधी फाउंडेशन जिसकी प्रमुख संयोग से सोनिया गांधी हैं, द्वारा पुरस्कृत होने के आधार पर खुद को सर्वोत्तम शासित राज्य होने का दावा कर रही है। यदि ऐसा होता तो स्वयं कांग्रेस पार्टी का भी लक्ष्य होता कि वह बी.जे.पी. की तरह मो. अली जिन्ना की धर्मनिरपेक्षता की खोज करें। लेकिन अब तक न राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात को भारत के सर्वोत्तम शासित राज्य होने को प्रमाणित किया है और न ही आडवानी ने जिन्ना की धर्मनिरपेक्षता को साबित किया है। लेकिन हम लोग प्रचारित सच्चाई पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में मोदी सरकार को ''आर्थिक स्वतंत्रता'' के आधार पर सबसे बेहतर बताया गया है और वह उसी का लाभ उठाना चाह रहे हैं। लेकिन वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता है क्या?

आर्थिक स्वतंत्रता के सिद्धांत की उत्पत्ति 1986–94 के बीच मिल्टन और रोज फ्रैडमैन द्वारा आयोजित तथा फ्रेजर इंस्टीटयूट ऑफ कनाडा द्वारा प्रायोजित सेमिनारों की एक श्रृंखला के दौरान हुई थी। मिल्टन फ्रीडमैन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और अर्थशास्त्र की दुनिया में कट्टर दक्षिणपंथी माने जाते हैं। जनता के प्रति संवेदनशील और केवल लाभ के प्रति समर्पित उनकी आर्थिक नीतियों की अनेक अर्थशास्त्रियों, जिनमें जॉन गैलब्रेच और अमर्त्यसेन भी शामिल हैं, ने आलोचना की है। मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा अपनाये गये अर्थशास्त्र को शिकागो स्कूल के रूप में भी जाना जाता है और इसका सबसे सच्चा चेला चिली का अगस्तो पिनोचट (Augush Pinochet) था। आर्थिक स्वतंत्रता के अन्य प्रमुख प्रस्तावक समर्थक अमेरिका के दो अत्यधिक रुढ़िवादी चिंतन केंद्र हेरिटेज फाउन्डेशन और काटो इन्स्टीट्यूट है। इसीलिए यह बहुत विडम्बनापूर्ण है कि भारत में इन अतिदनिवपंथी सिद्धांतों की वकालत राजीव गांधी फाउंडेशन की एक इकाई, राजीव गांधी इन्स्टीटयूट ऑफकॉन्टेम्पररी स्टडीज (RGICS)

द्वारा किया जा रहा है। वैसे आर्थिक स्वतंत्रता के विषय में यू.पी.ए. की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के विचारों पर कोई भी आश्चर्य व्यक्त करेगा?

जबकि आर्थिक स्वतंत्रता को वॉल स्ट्रीट जरनल (Wall Street Journal), जो कि प्रसन्नतापूर्वक केवल अपनी ग्यारहवीं वर्षगांठ मना रहा है, द्वारा एक नवीनतम विचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तब यह एक कटु सच्चाई है कि यह पूरा का पूरा विचार मुक्त उद्यम और मुक्त बाजार की शीत युद्ध की विचारधारा का बदला रूप है। जो कुछ भी हो यह ऐसी अर्थशास्त्रीय शब्दावली नहीं है जो अर्थशास्त्र के एम आई टी शब्दकोश वाली मेरी कॉपी में स्थान पाती। वास्तव में यह कुछ भी नहीं है लेकिन अति दक्षिणपंथियों द्वारा समर्थित एक खास किस्म की राजनीति इसे एक विचारधारात्मक जीवन पद्धति के रूप में बढ़ावा दे रही है। स्वयं फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने इसकी बेहतर रूप में इस प्रकार व्याख्या की है–''आर्थिक स्वतंत्रता उस स्थिति का विस्तार है जब कोई सरकार के हस्तक्षेप विना अपनी आर्थिक गतिविधियां को जारी रख सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत चयन, स्वैच्छिक विनिमय आय जो कुछ भी कमा रहे हैं उसको रखने के अधिकार और आपके संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, के आधार पर खड़ी होती है।'' इसका सीधा मतलब यह है कि अच्छी सरकार वह है जो अमीरों को वह सब करने दे जो वे चाहें, वे जो भी लेना चाहें लेने दें, वे जो रखना चाहें रखने दें और आम जनता भांड़ में जाय। संक्षेप में, बाजर सारी चीजों को तय करेगा। यह विचारधारा कुछ उसी तरह एकतरफा है जैसे यह कहना कि राज्य ही सबकुछ है और वही सबका ध्यान रखेगा।

आर्थिक स्वतंत्रता की वार्षिक विश्व रिपोर्ट आर्थिक स्वतंत्रता नेटवर्क के सदस्यों के सहयोग से फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित की गयी, जिसमें विश्व के तमाम देशों को आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया। संयोग से राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कान्टेम्परारी स्टडीज (RGICS) इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तब यह

प्रश्न उठता है कि वह नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करते जैसे तर्कहीन कार्यों में क्यों शामिल हैं? पिछले वर्ष की सूची में बेहमास, बेलिजी, घाना, तंजानिया और ट्यूनिशिया के साथ भारत 68 में स्थान पर था। इस सूचि में भारत यू ए ई (16), कुवैत (18), ओमान (18), एल सल्वाडोर (27), पनामा (27) और जार्डन (38) जैसे कुछ वास्तविक स्वतंत्र देशें से नीचे थे। अतः ऐसा लगता है कि यह आर्थिक स्वतंत्रता वैयक्तिक आजादी का महत्व सर्वाधिक है। 10 के पैमाने पर प्रथम स्थान प्राप्त हांगकांग को भी केवल 8.7 अंक दिया गया है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को 8.2 अंक मिला है। इससे स्पष्ट है कि पूंजिवाद के लिए विख्यात इन केन्द्रों के लिए भी आर्थिक स्वतंत्रता के निर्माताओं द्वारा बनाये गये मानदण्ड बहुत अधिक ऊँचे हैं। ऐसा लगता है कि वॉल स्ट्रीट जरनल के मानदण्ड हेरिटेज फाउन्डेशन से थोडे भिन्न हैं लेकिन अंततः ये एक ही निर्णय पर पहुंचते हैं। इसलिए जहां ये अपनी सूची में सउदी अरब को अत्यधिक मुक्त देश के रूप में शामिल करते हैं वहीं भारत को चीन की तरह अत्यधिक बंद देश के रूप में देखते हैं।

अब नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर वापस लौटें जिसने एक पूरे पेज के विज्ञापन द्वारा यह दावा किया है कि गुजरात भारत का सर्वोत्तम शासित राज्य है।

जो आर.जी.आई.सी.एस. अध्ययन के हवाले से गुजरात के बारे में कहा जा रहा है वह सत्य के निकट भी नहीं है।

''आर्थिक स्वतंत्रता'' अच्छी सरकार की पहचान नहीं है। यह तो आर्थिक सफलता की भी पहचान नहीं है। यह तो सरकार की कम–से–कम सक्रियता और उसकी व्यापार के प्रति अत्यधिक दोस्ताना रवैये को ही प्रकट करता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी पुलिसवाले का मूल्यांकन उसकी कार्यकुशलता के आधार पर नहीं बल्कि उसकी चमकदार और साफ वर्दी के आधार पर किया जाए। पिछले दशक के दौरान गुजरात की आर्थिक और सामाजिक विकास की उपलब्धियां स्वयं को श्रेष्ठ शासित राज्य बताने

वाले उनके विज्ञापन का समर्थन नहीं करती हैं। सन् 1993–94 के बाद के दशक में नियत मूल्य दर 6.72 प्रतिशत रहा है जो सूची में प्रथम स्थान प्राप्त पश्चिम बंगाल के 8.55 प्रतिशत और कर्नाटक के 7.29 प्रतिशत से काफी नीचे है। वास्तव में गुजरात का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 0.15 प्रतिशत नीचे और बिहार से केवल 0.10 प्रतिशत अधिक है। हम सभी जानते हैं कि बिहार आर्थिक विकास की बदहाली का कारण केन्द्र सरकार की सद्भावना की कमी अथवा राज्य सरकार के उचित प्रयासों का न होना है। इस प्रकार बिहार को अलग कर दिया जाय तो गुजरात अंतिम स्थान पर आ जाता है। गरीबी में कमी के मामले में 1977 से गुजरातने 65.87 प्रतिशत की अवनति (ह्रास) दिखायी है जो इसे प्रशंसनीय ढंग से छठा स्थान देता है। इससे ऊपर गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब हैं। यहाँ तक कि कुछ बहुत अच्छी सरकारों विशेष रूप से केशूभाई पटेल, सुरेश भाई मेहता और नरेन्द्र मोदी जैसी महान सरकारों के बावजूद गरीबी रेखा के नीचे 14.07 प्रतिशत जनता का होना इसे ऊपर से चौथा स्थान प्रदान करता है। जबकि गुजरात में सड़क और सिंचाई के लिए प्रति व्यक्ति खर्च भारत में सर्वाधिक है फिर भी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में इसका स्थान छठा है।

ये सारे परिणामों, मानव विकास सूचकांकों में भी देखा जा सकता है। शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी के मामले में गुजरात ने 17.94 प्रतिशत की कमी दर्ज कीहै जिसके आधार पर इसका स्थान ग्यारहवाँ है। 64 शिशु मृत्यु दर केसाथ यह सातवें स्थान पर है। जीवन प्रत्याशा के मामलों में भी गुजरात की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।62.15 वर्ष औसत उम्र के साथ यह बिहार से भी नीचे आठवें स्थान पर है। बिहार में औसत उम्र 62.85 वर्ष है। पुनः लिंगानुपात के मामले में भी गुजरात, 921 महिला प्रति 1000 पुरुष के अनुपात के साथ बिहार के कंधेसे कंधा मिला रहा है। साक्षरता दर के मामले में भी 69.97 प्रतिशत के साथ गुजरात सर्वोत्तम से काफी दूर है और इसका स्थान छठा है। जब इसे कुल जनसंख्या वृद्धि के पैमाने पर रखते हैं तब गुजरात 2.42 प्रतिशत वार्षिक

वृद्धि के साथ एक बार फिर छठा स्थान पाता है। यहां तक कि 5–14 वर्ष उम्र के बच्चों के स्कूल में नामांकन के मामले में भी गुजरात 74.35 प्रतिशत के साथ छठा स्थान पाता है।

आर.जी.आई.सी.एस. आर्थिक स्वतंत्रता के अध्ययन में स्पष्ट रूप से 'सम्पूर्ण जांच सुनिश्चित करने वाली दक्ष एवं प्रभावी कानूनी व्यवस्था' को पैमाने के रूप में शामिल करता है। शायद उन्होंने गोधरा कांड पर जस्टिस बनर्जी की रिपोर्ट या 130 कैदियों को उसी आरोप के दोष से पोटा से मुक्त करने के एस.सी.जैन की सेंट्रल पोटा रिव्यू कमिटी के आदेश पर विचार नहीं किया। दंगे में हजारों लोगों की हत्या और बेस्ट बेकरी कांड के विभिन्न नाटक गुजरात में कानूनी व्यवस्था की दक्षता और प्रभावीपन के अतिरिक्त प्रमाण हैं। जैसा कि 'देश में संपत्ति और जीवन की सर्वोत्तम सुरक्षा और हिंसक अपराधों के न्यूनतम प्रभावों का दावा गुजरात सरकार कर रही है। इस प्रकार न्यूनतम व्यवस्था रखने वाले गुजरात के साथ कोई कठिनाई से ही होड़ ले सकता है।
यह एक और परिप्रेक्ष्य है जिसके आधार पर भी हम गुजरात पर विचार कर सकते हैं। 2003 के दौरान संपत्ति मूल्य चुराने के मामले में 32,419 लाख रुपये के साथ गुजरात महाराष्ट्र के ठीक नीचे था। धन वसूली के मामले में गुजरात का औसत मात्र 9.5 प्रतिशत है जबकि प्रथम स्थान पर स्थित हरियाणा 68.3 प्रतिशत वसूलने में सफल रहा। गुजरात के बारे में एक और दिलचस्प आंकड़ा जो बहुत कुछ बता रहा है, वह यह हे कि 2003 में अपहरण के 1044 केस गुजरात में दर्ज किए गए जो अपहरण के लिए विख्यात राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दर्ज केसों की तुलना में करीब आधे हैं किन्तु मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक से काफी अधिक है। लेकिन जो बात गुजरात को वास्तव में विशिष्ट बनाती है वह यह है कि अपहरण किए गए लोगों में से लगभग 90 प्रतिशत तीस वर्ष से कम उम्र के हैं और लगभग 80 प्रतिशत अपहृत औरतें हैं। यह संख्या राष्ट्रीय औसत का लगभग दुगुनी है। 'जीवन और सम्पत्ति की सबसे अच्छी सुरक्षा' का दावा करने वाले गुजरात का सच है कि 13.1

प्रतिशत हिंसक अपराधों के साथ गुजरात उत्तर प्रदेश, प. बंगाल और पंजाब से भी आगे शर्मनाक स्थिति में खड़ा है। आई.पी.सी अपराध दर के मामले में गुजरात 160.7 के राष्ट्रीय औसत से आगे था।

कुछ और पैमानों पर भी हम विचार कर सकते हैं। कुल औद्योगिक मूल्य जोड़ के मामले में गुजरात का स्थान महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरा है। इसने 1993–94 से विद्युत उत्पादन में वृद्धि के मामले में केवल 18.69 प्रतिशत वृद्धि के साथ दयनीय प्रदर्शन किया, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि 43.75 प्रतिशत थी। वास्तविकता यह है कि बड़े राज्यों में यह केवल बिहार से आगे है। बिल्कुल स्पष्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी अच्छे प्रशासन का होना है। गुजरात ने बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं किया है परंतु भारत के 'सर्वोत्तम शासित राज्य' का दावा कुछ फर्जी आंकड़ों (सूचियों) पर आधारित है और सच के साथ हेरा–फेरी है।

MOHAN GURUSWAMY
3515 DLF 4, Gurgaon 122002, Haryana
Email: mguru@satyam.net.in